बरौली में पहली बार छठ गीत 'अरगिया के बेर' की हुई शानदार शूटिंग

औरंगाबाद (आससे)। बारुण प्रखंड के बरौली गांव में मंगलवार को छठ पूजा के गीत 'अरगिया के बेर' की शानदार शूटिंग की गई। शूटिंग का कार्यक्रम गांव के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर छठ घाट, बाबा कुटी, हनुमान मंदिर सहित कई प्रमुख स्थलों पर आयोजित किया गया। गांव की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान से जुड़े इन स्थलों पर गीत की शूटिंग होने से कार्यक्रम और भी खास बन गया।इस छठ गीत को बरौली गांव के ही दो बाल कलाकार राम और श्याम ने बेहद सुंदर अंदाज में गाया है। दोनों की मधुर आवाज और शानदार प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। गीत के माध्यम से छठ महापर्व की आस्था और लोक संस्कृति को खूबसूरती से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया।बरौली गांव में पहली बार इस तरह के छठ गीत की शूटिंग होने से ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। शूटिंग देखने के लिए गांव के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे और कलाकारों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों बाल कलाकारों को खूब बधाइयां और शुभकामनाएं दीं।इस आयोजन की खास बात यह रही कि गांव के ही दो छोटे बालकों ने अपनी प्रतिभा के दम पर बरौली को एक नई पहचान दिलाने की पहल की है। स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और गांव की कला, संस्कृति एवं परंपराओं को आगे बढ़ाने की यह एक सराहनीय कोशिश है।

ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि राम और श्याम भविष्य में भी इसी तरह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर बरौली गांव का नाम रोशन करेंगे।

कृषि यांत्रिकरण मेले का हुआ शुभारंभ

औरंगाबाद (आससे)। संयुक्त कृषि भवन, औरंगाबाद के प्रांगण में दो दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला (04 एवं 05 नवम्बर, 2026) का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.), सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्री गौरव सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी श्री संदीप राज, उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) डॉ. सोनू कुमार, जिला उद्यान पदाधिकारी डॉ. श्रीकांत एवं सहायक निदेशक, रसायन श्री अंशु राधे द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस अवसर पर उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), औरंगाबाद डॉ. सोनू कुमार ने कृषि यांत्रिकरण योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि खेती को आसान, कम खर्चीला एवं अधिक उत्पादक बनाने में आधुनिक कृषि यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को व्यापक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में औरंगाबाद जिले के किसानों के लिए प्रथम केंद्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कुल 767 कृषि यंत्रों के परमिट निर्गत किए गए हैं, जिनके लिए लगभग 276.00 लाख रुपये की अनुदान राशि निर्धारित है। इसके अतिरिक्त कस्टम हायरिंग के अंतर्गत 06, कृषि यंत्र बैंक के अंतर्गत 01 तथा स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत 07 किसानों को परमिट निर्गत किए गए हैं। किसानों को आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए कुल 86 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।

मेले के दौरान जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने विभिन्न कृषि यंत्रों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देते हुए किसानों को इन यंत्रों के उपयोग एवं सरकारी अनुदान योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया।

उन्होंने फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में किसानों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

आधुनिक कृषि में कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकरण योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कृषि यंत्रों के उपयोग से विशेषकर लघु एवं सीमांत किसान समय पर कृषि कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से फसलों को सुरक्षित रखने में भी सहायता मिलेगी। धान, गेहूं, दलहन, तेलहन एवं उद्यानिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए गुणवत्तायुक्त आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे खेती की उत्पादन लागत में कमी आने के साथ-साथ उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जिले में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रा रीपर, स्ट्रा बेलर, पैडी ट्रांसप्लांटर, सुपर सीडर, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, जीरो टिलेज मशीन, रोटावेटर, रीपर कम बाइंडर, मिनी राइस मिल, दाल मिल एवं ऑयल मिल सहित विभिन्न आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन यंत्रों के माध्यम से कृषि कार्यों में श्रम एवं समय की बचत के साथ उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि की संभावना है।

कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र कुमार, उप परियोजना निदेशक, आत्मा एवं श्रीमती सुप्रिया कुमारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा मंच संचालन किया गया। तकनीकी सत्र में कृषि विभाग के सहायक निदेशकों तथा कृषि विज्ञान केंद्र, सिरिस के वरीय वैज्ञानिक-सह-प्रधान श्री विनय कुमार मंडल एवं वरीय वैज्ञानिक श्री पंकज कुमार सिन्हा द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की उपयोगिता, संचालन एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कृषि यांत्रिकरण मेला दिनांक 05 नवम्बर 2026 तक जारी रहेगा, जिसमें किसान आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ अनुदान संबंधी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कैमूर का धूमधाम से मना 14वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना

भभुआ/कैमूर (आससे)। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कैमूर का 14वां स्थापना दिवस बुधवार को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी कुमार अनुराग ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता शशिकांत कुमार ने डीएम सहित अन्य अतिथियों को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।समारोह में विद्युत विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को जिलाधिकारी के हाथों प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने से कर्मियों में उत्साह दिखा। कार्यक्रम स्थल पर सोलर प्लेट की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग और उसके लाभों की जानकारी दी गई। साथ ही घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित किया गया।

समारोह को संबोधित करते हुए डीएम कुमार अनुराग ने कहा कि एक समय जिले में महज तीन से चार घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब आपूर्ति व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। यह विभागीय अधिकारियों और कर्मियों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अब लक्ष्य उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना होना चाहिए। इसके लिए विभाग को लगातार व्यवस्था में सुधार करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना होगा।मौके पर एडीएम, एसडीपीओ, एसडीएम सहित विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

बिहार सरकार

कार्यालय, कार्यपालक अभियन्ता
पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली, सुपौल
निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 01/2026-27
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
पत्रांक–1253

1. कार्य का विवरण :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (लाख रू0 में) (ऑनलाईन अथवा फिजिकल/मैनुअल मोड में भुगतेय) (लाख में)	परिमाण–विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय) (रू0 में)	बेल्ट्रॉन को देय "बीड प्रोसेसिंग फी" (अप्रत्यर्पणीय) केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली, सुपौल के अन्तर्गत निर्मली घोघरडीहा लिंक रोड़ का कि0मी0 0.00 से कि0मी0 3.09 तक निर्माण कार्य।	₹712.68	₹14.26	₹10000.00	₹11800.00	31.10.2027
2.	पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, निर्मली, सुपौल के अन्तर्गत भारदा के नीचे तिलयुगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य।	₹1465.27	₹24.66	₹10000.00	₹11800.00	31.10.2027

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :- दिनांक–30.10.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने एवं निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय :- दिनांक–18.11.2026 के 03:30 बजे अपराह्न से दिनांक–28.11.2026 के 3:00 बजे अपराह्न तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. प्री बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि :- दिनांक–21.11.2026 के 03:30 अपराह्न मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर के कार्यालय।
5. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक–28.11.2026 समय 04:00 P.M (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :- सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
7. निविदा खोलने का स्थान :- www.eproc2.bihar.gov.in पर।
8. निविदा की वैधता की अवधि :- 120 दिन
9. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल।
10. ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिसके लिए उन्हें उपयोग कर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in डाउन लोड करने/ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
11. निविदा मात्र वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 014749 (WRD) 2026-27

कार्यपालक अभियंता,
पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली, सुपौल
मो0–06473357377

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
3rd floor, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura
Adjacent to State Health Society, Patna 800014,
Phone/Fax: +91612 2283287,+ 91612 2283288

Govt. of Bihar

(Notice Inviting E-Bids)

Tender for the Procurement, Rate Contract and Supply of Medical Equipment for different Govt. Health Institutions of Bihar.
Notice Inviting Tender No.-BMSICL/2026-27/ME-518Dated: November 2026
(Only through E- Tender on website:-https://eproc2.bihar.gov.in)

The Bihar Medical Services and Infrastructure Corporation Limited, Patna invites e-bids from interested parties for Procurement, Rate Contract and supply of Medical Equipmentfor different Government Health Institutions of Bihar as listed below:-

1	Cardiotocography (CTG) Machine (AI Enabled)

Tender Schedule

Tender Reference No.	BMSICL/2026-27/ME-518
Date of Pre- Bid Meeting	12thNovember 2026 at 15:00 Hrs in Conference hall of BMSICL, 3rd Floor, Swasthya Bhawan, IGIMS Campus, Sheikhpura, Patna (Bihar) All Pre-bid queries to be submitted through e-mail onbmsicltenderequipment@gmail.com Upto 14thNovember 2026 till 17:00 Hrs. (Note:- No Pre-bid queries would be entertained after the above mentioned dead line)
Last date and time of submission of online bids	08thDecember2026 upto 17:00 Hrs.
Last date and time for submission of original documents of EMD.	09thDecember2026 upto 14:00 Hrs.
Date, Time and Place of opening of Technical Bid	09thDecember 2026 (at 15:00 Hrs.) on the website of https://eproc2.bihar.gov.in the office of BMSICL
Date and time of opening of financial Bids	To be announced later on https://eproc2.bihar.gov.in
Validity of Tender	180 Days
Cost of the tender document	Rs.11,800/- (Eleven Thousand Eight Hundred Rupees only) Non-refundable.
Tender Processing Fee	Rs 1180/- (on the website of https://eproc2.bihar.gov.in)

1. To participate in E-Tendering the tenderer will have to be registered with E-Tendering service provider. For this help desk – mjunction services limited RJ complex, 2nd Floor, Canara Bank, Campus, khajpura, Ashiana Road, P.S –Shastri Nagar, Patna-800014, Toll Free No.-18005726571, Email-ID: can be approached.
2. Any queries and questions regarding the tender should be addressed to MD BMSICL (either through letter or through e-mail:- and/or bmsicl.equipment@gmail.com or contact no. 0612-2219634/35) up to 7 days before of closing of online bid registration.
3. All communication, addendum/corrigendum related to this tender will be issued on the website of
4. Managing Director, BMSICL reserves the right to reject any or all the applications without assigning any reason.

Note- Changes suggested by prospective bidder in Pre-Bid meeting may be incorporated in the tender document at the sole discretion of the tender inviting authority and for which corrigendum will be issued separately and uploaded on the website &www.bmsicl.gov.in

GM (Procurement)
BMSICL, Patna

PR- 014798 (B & C) 2026-27

For further details please visit : www.state.bihar.gov.in/prdbihar

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार

प्रथम पृष्ठ का शेष

नीतीश के सपने को तेजी से...

उनके सपनों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने त्योहारों में बिहार आने वाले लाखों यात्रियों की परेशानी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्री से मुलाकात कर छठ और दिवाली के दौरान बिहार के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का आग्रह किया गया है।सम्राट चौधरी के मुताबिक, पिछले साल 10 हजार से अधिक जोड़ी ट्रेनें चलाई गई थीं। इस बार इससे भी अधिक ट्रेनें चलाने की मांग की गई है, ताकि दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकें और छठ महापर्व अपने परिवार के साथ मना सकें।

बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। अब मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी। सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में करीब 13 हजार एकड़ जमीन उद्योगों के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक एक हजार से अधिक उद्योगों को जमीन दी जा चुकी है। सरकार आगे भी निवेशकों को बिहार से जोड़ने का काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने बिहार में डेटा सेंटर परियोजना को भी बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में सरकार बनने के बाद इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की पहल की गई थी। पटना में संबंधित परियोजना का उद्घाटन भी किया गया और अब डेटा सेंटर का काम शुरू हो चुका है।उनका कहना है कि बिहार में उद्योग और तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

औद्योगिक कॉरिडोर और पर्यटन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। उन्होंने बिहार में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन परियोजना के लिए जल्द पर्यावरणीय मंजूरी देने का आग्रह किया।सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन की व्यवस्था दी और संगठित अपराध को खत्म करने की दिशा में काम किया। उनकी सरकार उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी।

सम्राट चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है. उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार से इस पर सहमति मिलेगी.

उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक एक हजार से अधिक उद्योगों को जमीन दी जा चुकी है. राज्य में डाटा सेंटर भी बनकर तैयार हो गया है. सरकार का प्रयास है कि बिहार में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हों.

नीतीश से मिलने पहुंचे...

दी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि वह तीन दिनों तक दिल्ली में थे. इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई. पटना लौटने के बाद वह सीधे नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे.

सम्राट चौधरी ने कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई देने आए थे. प्रधानमंत्री की ओर से भी उन्हें बधाई दी गई है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में गाद नीति का मुद्दा लगातार उठाया था. अब उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है. उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्र सरकार के साथ विभिन्न नदियों से करीब चार लाख घन मीटर गाद निकालने को लेकर समझौता हुआ है.

उन्होंने बताया कि पथ परिवहन विभाग के माध्यम से भी समझौता किया गया है. इससे बिहार में बाढ़ की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी. नदियों से गाद निकालने का फायदा किसानों को भी होगा. खेतों की मिट्टी के कटाव से बचाव हो सकेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के सुशासन और विकास के कामों को उनकी सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है.

दिल्ली दौरे के दौरान सम्राट चौधरी ने रेल मंत्री से भी मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने आगामी छठ महापर्व को लेकर बिहार के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल 10 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं. इस बार उन्होंने इससे भी ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया है. बिहार में छठ के दौरान बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से अपने घर लौटते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मस्थली है. वहीं, सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली है. दोनों धार्मिक स्थलों को रेल मार्ग से सीधे जोड़ने की जरूरत है. इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर भी कई जानकारियां दीं. उन्होंने बताया कि गया में आईएमसी के तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है. इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत हुई है.

नशे के कारोबार में...

फिलहाल सहायक पुलिस अधीक्षक फुलवारीशरीफ नारायण उपाध्याय पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि नशे के कारोबार से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम में किन-किन लोगों की भूमिका रही है और कथित लेन-देन में कौन-कौन शामिल था.

75% की आर्मी में होगी...

अत्याचार हो या अगली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए कोई खतरा हम सख्त और निर्णायक कदम उठाएंगे. इसमें मौजूदा कानूनों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना, जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाना और कानूनों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना शामिल है.

मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की...

जा रही है। सूचना के बाद एएसआई नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने बेला फेज-2 के नारायणपुर रोड में छापेमारी की, जहां सड़क किनारे एक संदिग्ध ट्रक खड़ा मिला। ट्रक चालक भी मौके पर मौजूद था।

शुरुआत में चालक ने ट्रक में ट्रांसपोर्ट का सामान होने की बात कही। हालांकि, सख्ती से पूछताछ करने पर उसने ट्रक में शराब होने की जानकारी दी। इसके बाद ट्रक का पिछला हिस्सा खुलवाया गया। अंदर कागज और कार्टन के टुकड़ों से भरी बोरियां रखी थीं। जब इन बोरियों को हटाया गया तो नीचे छिपाकर रखे गए शराब के कार्टन देखकर उत्पाद विभाग की टीम भी हैरान रह गई। गिरफ्तार चालक की पहचान पंजाब के फतेहगढ़ जिले के खमानोल निवासी मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि वह पंजाब से शराब की खेप लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचा था। यहां अलग-अलग जगहों पर शराब अनलोड की जानी थी। चालक के अनुसार, उसे बेला में ट्रक रोकने का निर्देश दिया गया था, जहां मुख्य शराब कारोबारी पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लेने वाला था। एक खेप पहुंचाने के बदले उसे 10 हजार रुपये देने की बात तय हुई थी।

उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पंजाब नंबर के ट्रक को पकड़ा गया है। ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसका मिलान कराया जा रहा है। चालक से पूछताछ कर स्थानीय शराब तस्करों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं, शराब की खेप मंगाने वाले मुख्य धंधेबाज और स्थानीय तस्करों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई जारी है।

50 संस्कृत स्कूल बनेंगे...

सामाजिक दायित्व के माध्यम से अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब स्थापित की जायेगी। इन लैबों में आधुनिक कंप्यूटर एवं आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इससे अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल तकनीक और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से जोड़ने का अवसर मिलेगा। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने बताया कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य में 50 मॉडल संस्कृत विद्यालय विकसित करने की परिकल्पना की गयी है। इस दिशा में सीएसआर के माध्यम से छह विद्यालयों में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब की स्थापना पहला महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में इस अभियान को और व्यापक स्वरूप दिया जायेगा तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों, केंद्रीय उपक्रमों एवं कॉर्पोरेट संस्थाओं के सहयोग से संस्कृत विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण को आधुनिक बनाया जायेगा। ध्यक्ष ने कहा कि यह पहल न केवल संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए नये अवसरों के द्वार खोलेगी, बल्कि बिहार में संस्कृत शिक्षा के आधुनिकीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मॉडल विद्यालयों की स्थापना के संकल्प को भी नयी गति प्रदान करेगी।

एमएलसी चुनाव में हार के...

संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा करेंगे. इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे. चुनाव में उतरे सभी उम्मीदवारों को बैठक में बुलाया गया है. संबंधित जिलों के अध्यक्षों को भी अपनी रिपोर्ट के साथ शामिल होने को कहा गया है.पार्टी नेतृत्व चुनाव के नतीजों को गंभीरता से ले रहा है. बैठक में हर सीट पर पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा होगी. इसके साथ ही संगठन की भूमिका और चुनाव प्रचार के दौरान सामने आई कमियों पर भी चर्चा की जाएगी.

विधान परिषद चुनाव में तीन सीटों पर मिली हार के बाद जेडीयू अब अंदरूनी कमियों का पता लगाना चाहती है. पार्टी यह जानने की कोशिश करेगी कि किन इलाकों में संगठन ने अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं किया. चुनावी रणनीति में कहां चूक हुई और उम्मीदवारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा.जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट इस बैठक में अहम हो सकती है. उनके जरिए स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, चुनावी माहौल और सहयोगी दलों के साथ तालमेल की जानकारी ली जाएगी. चुनाव के दौरान जिन नेताओं की भूमिका पर सवाल उठे हैं, उनकी जिम्मेदारी पर भी चर्चा होने की संभावना है.

सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवारों की हार पार्टी के लिए बड़ा सवाल है. इन दोनों सीटों पर चुनावी नतीजों को लेकर पार्टी के भीतर मंथन हो सकता है.

चुनाव के दौरान जेडीयू उम्मीदवारों की ओर से सहयोगी दलों के समर्थन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे. ऐसे में बैठक में गठबंधन के भीतर तालमेल की स्थिति पर चर्चा हो सकती है. पार्टी नेतृत्व यह समझना चाहेगा कि सहयोगी दलों के साथ समन्वय की कमी का नतीजों पर कितना असर पड़ा. अनंत सिंह ने जेडीयू की बैठक में भी नीरज कुमार के लिए वोट नहीं मांगने की बात कही थी. पार्टी ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए उन्हें छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था. उनकी पत्नी नीलम देवी की सदस्यता भी वापस ले ली गई.अब समीक्षा बैठक में पटना स्नातक सीट के चुनावी घटनाक्रम पर भी चर्चा हो सकती है. पार्टी यह भी समझने की कोशिश करेगी कि अंदरूनी विरोध का चुनाव पर क्या असर पड़ा.

विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने जेडीयू के सामने संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. पटना स्नातक सीट की जीत के बावजूद तीन सीटों पर मिली हार पार्टी के लिए चिंता का विषय है. ऐसे में 5 नवंबर की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है. इस दौरान सिर्फ हार-जीत के आंकड़ों पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में चुनावी चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है.

पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के...

एसवीयू की टीम विभिन्न परिसरों में तलाशी और जांच की कार्रवाई कर रही है। छापेमारी पूरी होने के बाद ही बरामद नकदी, दस्तावेजों और अन्य संपत्तियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

60000 पीडीएस दुकानों का डिजिटल...

जा रहा है. बताया जा रहा है कि राशन दुकानों पर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पास) मशीनों को आधार आधारित बायोमीट्रिक और ओटीपी प्रमाणीकरण से जोड़े जाने की तैयारी है.

दो से ज्यादा बच्चे होने पर...

मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की सिफारिश की है. इस मामले में तीन जजों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने से उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के प्रावधान को संवैधानिक रूप से सही माना था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत बताई है.

दरअसल, साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने %जावेद बनाम हरियाणा राज्य% मामले में दो बच्चों की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी. उस समय अदालत ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी, जिसके तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता था. इस फैसले के बाद कई राज्यों में इसी तरह के प्रावधान लागू रहे. अब मौजूदा पीठ का मानना है कि बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में उस फैसले के आधार की फिर से समीक्षा होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत की कुल प्रजनन दर यानी कुल प्रजनन दर (ञ्झ्रक्र) में आई गिरावट को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया. अदालत के मुताबिक, साल 2003 में भारत की कुल प्रजनन दर 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। जबकि 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट रेट यानी प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है. इसका मतलब है कि इस दर पर एक पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से जनसंख्या के स्तर पर खुद को प्रतिस्थापित कर सकती है.

अदालत ने कहा कि भारत की प्रजनन दर अब प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच चुकी है. हालांकि, देश की कुल आबादी में अभी गिरावट नहीं आई है, लेकिन प्रजनन दर का लगातार कम होना भविष्य में बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव का कारण बन सकता है. इससे बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और कामकाजी उम्र के लोगों की हिस्सेदारी घटने की आशंका है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, इन बदलावों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों से अधिक होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानूनों के पीछे दिए गए तर्कों पर भी सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि ऐसे कानून लागू रहने से नागरिकों का एक पूरा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर हो जाता है, जबकि दो से अधिक बच्चे होने का किसी व्यक्ति की सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से सीधा संबंध नहीं है. पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिबंध लोगों को बच्चे पैदा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के बीच अनुचित चुनाव करने के लिए मजबूर करते हैं. अदालत के मुताबिक, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन करने वा